











## केंद्र को झटका: खनिज कर्दे पर फैसला राज्यों के हक में

आधिकारिक केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों की कानूनी लड़ाई तार्किक परिणाम तक पहुंच ही गई है। देश की शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है कि किसी भी राज्य के खनिजों पर देश टॉयलटी एक कर नहीं है। साथ ही स्पष्ट किया कि राज्यों के पास खानों, खनिजों और खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी शक्ति निर्धारित है। दरअसल, इस सारे विवाद के मूल में खान और खनिज (विकास और विनियोग) अधिनियम, 1957 रहा है। इस अधिनियम का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की दलील थी कि केवल संसद ही खनिजों पर कर लगा सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बाबत फैसला सुनाया कि कानून राज्यों को खानों और खनिज विकास पर कर लगाने से प्रतिवधित नहीं करता है। निश्चित स्पष्ट से इस फैसले से प्राकृतिक संपदा से संपन्न गरीब राज्यों मरालन ज्ञारखंड और ओडिशा को विशेष स्पष्ट से लाभ होने की उम्मीद जगी है। ये राज्य केंद्र द्वारा खानों और खनिजों पर लगाये गए डाक्यों को लगाने की विधानी मांग करते रहे हैं। नियराटेह, यदि केंद्र सरकार राज्यों की माली हालत के गदेनजर उनकी जस्ती तथा आक्रामाओं के प्रति संवेदनशील होती तो निश्चित स्पष्ट से इस विवाद को बातीत के जिये सुलझाया भी जा सकता था। जब लंबे समय तक इस मामले का नियराट नहीं हो सका तो अन्ततः देश की शीर्ष अदालत को गतिरोध तोड़ने के लिये हस्तियों करना ही पड़ा। इसमें दो राय नहीं है कि केंद्र और राज्यों के बीच कई मुद्दे पर टकराव कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखने में आया है कि हाल के वर्षों में यह विवाद आम बात हो चला है। निश्चित स्पष्ट से किसी भी राष्ट्र की सीधी व्यवस्था के लिये ये टकराव व विवाद कोई शुभ संकेत तो करपि नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि कुछ मुद्दे सहमति, सामग्र्य और संवेदनशीलता से भी सुलझाए जा सकते हैं। जिससे राज्यों के आर्थिक संकट को भी दूर किया जा सकता है। दरअसल, इस बात पर गंभीर विराटी की जस्ती है कि हाल के वर्षों में केंद्र-राज्यों के बीच कलह के मामले लगातार वर्षों बढ़ते जा रहे हैं। नियराटेह, इस टकराव के राजनीतिक निहितार्थ भी है। इस विवाद को हाल में संसद में प्रस्तुत आम बजट के परिषेक में भी देखा जा सकता है। यहीं बजह है कि वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में राजग गठबंधन तें शामिल बिहार तथा आंध्र प्रदेश के लिये घोषित विशेष पैकेजों ने विषय को गैर भाग दिया है। विषय ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक स्पष्ट से पक्षपात वाला बजट बनाने का आरोप लगाया है। इनमें ही नहीं कई विषयों के मुख्यमन्त्रियों ने बजट में गेटवाय का आरोप लगाते हुए आगामी 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक तें शामिल न होने की बात कही है। जो कि केंद्र व राज्यों के बीच टकराव की अप्रिय स्थिति को ही दर्शाता है। यदि अतीत के पन्ने पलटें तो वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्थ में, सरकारिया आयोग ने सहकारी संघवाद के विद्वानों के आधार पर सामग्र्यपूर्ण संघ-राज्य संबंधों की जस्ती पर बल दिया था। वहीं दूसरी ओर सरकारिया आयोग ने चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया था कि देश में शक्तियों के अधिक केंद्रीकरण ने लोगों की समस्याओं का सामाधान करने की बजाय उसमें और वृद्धि कर दी है। केंद्र सरकार के लिये बेहतर होगा कि आयोग की रिपोर्ट पर पड़ी धूल को साफ करके उसका बेहतर बाईक व संवेदनशील ढंग से अध्ययन करे। इस तरह के आयोगों के बीच एक बात तो साफ है कि एक शक्तियाली केंद्र भारत जैसे विकासशील देश को विकासित भारत में कवापि होता है। वहीं केंद्र व राज्यों में सामग्र्य व संघवाद के लिये यहीं बदल रहे हैं। नियराटेह, यहीं केंद्र को ज्ञानी नियमिता देना चाहिए।

## अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सबला कमला

अरुण नैथनी

**इ**स साल के अंत में दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी से लगता है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की किसी भी चमक सकती है। अब तक राष्ट्रपति पद के लिये डोमेकेट प्रत्याशी के रूप में मजबूत दावेदारी कर रहे जो बाइडेन ने इस चुनावी दौड़ से अपने को अलग कर लिया है। बाइडेन ने वह कदम बढ़ाया उसे चलने तें पर रेस से बाहर होने के लिए बढ़ रहे दावाव के बीच उठाया। रिपब्लिकन क्रियाशील बहस में पिछड़ने के बाद लगता था कि उपराष्ट्रपति बाइडेन के मुकाबले ट्रंप से टीकी बहस में बेंकिन कमला हैरिस के डोमेकेटिक प्रत्याशी के रूप में सामने आने से तस्वीर बदल गई है। अब दूसरा बाइडेन की जगह सबसे ज्यादा उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बन गए हैं।

बहरहाल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन



आज भले ही कमला अमेरिका में प्रतिष्ठित अश्वेत नेता हों, लेकिन उन्होंने भारत से अपने जुड़ाव को कभी नकारा नहीं। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में जन्मी कमला ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री लेकर वकालत शुरू की। वर्ष 2014 में यहूदी वकील डिग्लास एम्पहॉप से यहूदी व भारतीय परंपराओं से विवाह रचाया। वैसे उनकी छवि अफ्रीकी अमेरिकी राजनेता के रूप में बनी है। एक वजह यह भी है कि बाइडेन ने अमेरिका में भारतीय व अफ्रीकी मूल के निर्णयक वोटों के मद्देनजर कमला की राष्ट्रपति पद की दावेदारी का समर्थन किया है। आज अमेरिका में कमला हैरिस की छवि एक उदार, आधुनिक मूल्यों की पक्षधर तथा मानवाधिकारों के लिये संघर्ष करने वाली महिला के रूप में बनी है। निससंदेह, कमला हैरिस एक मुख्य वक्ता और करिशमाई बहस करने वाली राजनेता हैं।

कमला की दावेदारी को महत्वाकांक्षी डोमेकेटेस की चुनौती मिल सकती है। अमेरिकी इतिहास में कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिये पहली अपेक्षा महिला वकालत है। डोमेकेटेस के लिये यह एक ऐसा जोखिम जो उन्हें उठाना पड़ता है। दरअसल, इस बात पर गंभीर विराटी की जस्ती है कि हाल के वर्षों में केंद्र-राज्यों के बीच कलह के मामले लगातार वर्षों बढ़ते जा रहे हैं। नियराटेह, इस टकराव के राजनीतिक निहितार्थ भी है। यहीं केंद्रीय बजट के प्रस्तुत आम बजट के परिषेक में भी देखा जा सकता है। यहीं बजह है कि वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में राजग गठबंधन तें शामिल बिहार तथा आंध्र प्रदेश के लिये घोषित विशेष पैकेजों ने विषय को गैर भाग दिया है। विषय ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक स्पष्ट से पक्षपात वाला बजट बनाने का आरोप लगाया है। इनमें ही नहीं कई विषयों के मुख्यमन्त्रियों ने बजट में गेटवाय का आरोप लगाते हुए आगामी 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक तें शामिल न होने की बात कही है। जो कि केंद्र व राज्यों के बीच टकराव की अप्रिय स्थिति को ही दर्शाता है। यदि अतीत के पन्ने पलटें तो वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्थ में, सरकारिया आयोग ने सहकारी संघवाद के विद्वानों के आधार पर सामग्र्यपूर्ण संघ-राज्य संबंधों की जस्ती पर बल दिया था। वहीं दूसरी ओर सरकारिया आयोग ने चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया था कि देश में शक्तियों के अधिक केंद्रीकरण ने लोगों की समस्याओं का सामाधान करने की बजाय उसमें और वृद्धि कर दी है। केंद्र सरकार के लिये यहीं बदल रहे हैं। नियराटेह, इस टकराव के राजनीतिक निहितार्थ भी है। यहीं केंद्रीय बजट के प्रस्तुत आम बजट के परिषेक में भी देखा जा सकता है। यहीं बजह है कि वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में राजग गठबंधन तें शामिल बिहार तथा आंध्र प्रदेश के लिये घोषित विशेष पैकेजों ने विषय को गैर भाग दिया है। विषय ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक स्पष्ट से पक्षपात वाला बजट बनाने का आरोप लगाया है। इनमें ही नहीं कई विषयों के मुख्यमन्त्रियों ने बजट में गेटवाय का आरोप लगाते हुए आगामी 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक तें शामिल न होने की बात कही है। जो कि केंद्र व राज्यों के बीच टकराव की अप्रिय स्थिति को ही दर्शाता है। यदि अतीत के पन्ने पलटें तो वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्थ में, सरकारिया आयोग ने सहकारी संघवाद के विद्वानों के आधार पर सामग्र्यपूर्ण संघ-राज्य संबंधों की जस्ती पर बल दिया था। वहीं दूसरी ओर सरकारिया आयोग ने चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया था कि देश में शक्तियों के अधिक केंद्रीकरण ने लोगों की समस्याओं का सामाधान करने की बजाय उसमें और वृद्धि कर दी है। केंद्र सरकार के लिये यहीं बदल रहे हैं। नियराटेह, इस टकराव के राजनीतिक निहितार्थ भी है। यहीं केंद्रीय बजट के प्रस्तुत आम बजट के परिषेक में भी देखा जा सकता है। यहीं बजह है कि वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में राजग गठबंधन तें शामिल बिहार तथा आंध्र प्रदेश के लिये घोषित विशेष पैकेजों ने विषय को गैर भाग दिया है। विषय ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक स्पष्ट से पक्षपात वाला बजट बनाने का आरोप लगाया है। इनमें ही नहीं कई विषयों के मुख्यमन्त्रियों ने बजट में गेटवाय का आरोप लगाते हुए आगामी 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक तें शामिल न होने की बात कही है। जो कि केंद्र व राज्यों के बीच टकराव की अप्रिय स्थिति को ही दर्शाता है। यदि अतीत के पन्ने पलटें तो वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्थ में, सरकारिया आयोग ने सहकारी संघवाद के विद्वानों के आधार पर सामग्र्यपूर्ण संघ-राज्य संबंधों की जस्ती पर बल दिया था। वहीं दूसरी ओर सरकारिया आयोग ने चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया था कि देश में शक्तियों के अधिक केंद्रीकरण ने लोगों की समस्याओं का सामाधान करने की बजाय उसमें और वृद्धि कर दी है। केंद्र सरकार के लिये यहीं बदल रहे हैं। नियराटेह, इस टकराव के राजनीतिक निहितार्थ भी है। यहीं केंद्रीय बजट के प्रस्तुत आम बजट के पर













जिज्ञासा ज्ञान की पहली सीढ़ी है

## पाकिस्तान को चेतावनी

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के रणबांधुओं और बलिदानियों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से सीधे-सीधे पाकिस्तान का नाम लेकर यह जो दो टूक ढंग से कहा गया कि आतंक के आकांक्षों के नापक मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा, वह समय की मांग थी। पाकिस्तान को ऐसा कोई कठोर संदेश देना इसलिए आवश्यक हो गया था, जोकि पिछले कुछ समय में वह जम्मू-कश्मीर में नए सिरे से आतंकवाद को खाड़-पानी देने में जुट गया है। इसकी प्रमाण जम्मू संभाग में हाल के आतंकी हाल हैं। इन हमलों में भारतीय सेना को जो ज्ञान उठानी पड़ी है, उसकी अनन्दिती नहीं की जानी चाहिए। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने एक ओर जहां कारगिल संघर्ष में भारत की विजय को धार किया, वहां दूसरी ओर पाकिस्तान की धोखेबाजी को भी विस्तार से रेखांकित किया। कारगिल में धूसपैठ पाकिस्तान के विश्वासधात का ही परिचयक थी। कारगिल में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को न केवल धूल चटाई थी, बल्कि अपनी कूटनीति से विश्व स्तर पर उसे शर्मसार भी किया था, लेकिन यह मानने के पर्यांत करण है कि उसने अपनी पराया और सामिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा।

पाकिस्तान ने भारत को धोखा देने की अपनी नीति का परिचय अभी भी नहीं किया है। वह न तो भारत से व्यापार कर रहा है और न ही एक अच्छा बहुकात स्तर के संबंध बहाल कर रहा है, लेकिन यह चाह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम वीथियंस ट्राफ़ी खेलने उसके बहां आए। इस चाहत का कोई अर्थ नहीं। सच्चाई यह है कि वह भारत से संबंध सुधारने का इच्छुक नहीं और दुनिया की भरमाने के लिए देसी क्षमता करने का दियावा कर रहा है। धोखेबाज पाकिस्तान से सतर्क रहने में ही समझवारी है। वह भले ही आर्थिक रूप से बदलाल हो, लेकिन भारत के लिए खतरा बने आतंकी समझौतों को पालने-पोसने का काम पहले की तरह ही कर रहा है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कठोर चेतावनी देकर बिल्कुल सही किया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उसने जम्मू-कश्मीर में जो छँड युद्ध छेड़ रखा है, उस पर अभी विजय पाना शेष है। यह समझा जाना चाहिए कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलाने से तब तक बाज आने वाला नहीं है, जब तक उसे इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। पाकिस्तान आतंकीयों को प्रशिक्षित कर भारत में आतंकी धूसपैठ करने की अपनी हक्रों इसीले जारी रखे हैं, क्योंकि उसे किए की उचित सज्जा नहीं दी जा रही है। उसके खिलाफ वैसी कोई कारबाह करने पर विचार किया जाना चाहिए, जैसी संरक्षित स्ट्राइक और एवर स्ट्राइक के माध्यम से की गई थी। पाकिस्तान केवल जम्मू-कश्मीर को असान एवं अस्थिर रखने का ही प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि यहां के साथ पंजाब और गज़ारान में ड्रोन के जरिये नशीले पदार्थ भी भेज रहा है।

## सुखद संकेत

बिहार सरकार स्कूली शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा पर भी काफी ध्यान दे रही है। इसी कीड़ी में राज्य में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेज खोले गए। शुरुआती दिनों में भले ही अशाऊनक परिणाम परिलक्षित नहीं हुए, किंतु धीरे-धीरे प्रयास रांग लगा रहा है। राज्य के 23 संकारी इंजीनियरिंग कालेजों के द्वारा-त्रिवृतीयों का टीएसएस कंपनी में नियोजन हुआ है। जाहिर है, एसे परिणामों से विद्यार्थियों का उत्साहर्वर्णन तो होता ही है। अभिभावकों का मनोबल भी बढ़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं होने के कारण काफी संख्या में यहां के विद्यार्थी दूसरे राज्यों के संस्थानों में दो खाली लेते हैं और फिर पढ़ाई

**विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**

**इससे और वेहतर परिणाम मिलेंगे**

विहार के तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक

**स्तर को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है।**



जिज्ञासा ज्ञान की पहली सीढ़ी है

## पाकिस्तान को घेतावनी

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के रणबांधुओं और बलिदानियों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से साथ-साथ पाकिस्तान का नाम लेकर यह जो दूक ढंग से कहा गया कि आतंक के आकांक्षों के नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा, वह समय की मांग था। पाकिस्तान को ऐसा कोई कठोर संदेश देना इसलिए आतंकवाद की गया था, क्योंकि पिछले कुछ समय से वह जम्मू-कश्मीर में नए सिरे से आतंकवाद को खाद-पान देने में जुट गया है।

इसका प्रमाण जम्मू-संभाग में हाल के आतंकवादी हमले हैं। इन हमलों में भारतीय सेना को जो क्षति उठानी पड़ी है, उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने एक ओर जहां कारगिल संघर्ष में भारत की विजय को याद किया, वहां दूसरी ओर पाकिस्तान की धोखेबाजी को भी विस्तार से रेखांकित किया। कारगिल में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को न केवल धूल चटाई थी, बल्कि अपनी कूटनीति से विश्व स्तर पर उसे शर्मसार भी किया था, लेकिन यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि उसने अपनी पराया और शमिदीरी से कोई सबक नहीं सोखा। पाकिस्तान ने भारत को धोखा देने की अपनी नीति का परिवर्त्यांक भी नहीं किया है। वह न तो भारत से व्यापार कर रहा है और न ही उच्चायुक्त स्तर के संबंध बढ़ावा कर रहा है, लेकिन यह चाह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम चैपिंस ट्रॉफी खेलने उसके बहाने आए। इस चाहत को कोई अर्थ नहीं। सच्चियां यह हैं कि वह भारत से संबंध सुधारने का इच्छुक नहीं और तुनिया के भ्रमणों के साथ कारने का दिखावा कर रहा है। धोखेबाज की अपनी हक्कतें इसलिए जारी रखे हैं, क्योंकि उसके किंवदं उत्तरांश के अर्थात् आतंकवादी को लेकर याद रखते हैं।

सेंटर पार द स्ट्रीट आप संसायटी में उत्तरांश के साथ-साथ धूम्रपान के लिए व्यापार करते हैं। यह भले ही प्रायंक भ्रमणों के साथ-साथ धूम्रपान के लिए खतरा बने आतंकी समूहों को पालने-पासने का काम पहले तो तरह ही कर रहा है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कठोर घेतावनी देकर बिल्कुल सही किया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उसने जम्मू-कश्मीर में जो छुट्टी छुट्टे रखा है, उस पर अपनी विजय पाना शेष है। यह समझा जाना चाहिए कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलने से तब तक बाज आने वाला नहीं है, जब तक उसे इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। पाकिस्तान आतंकवादों को प्रशिक्षित कर भारत में उनकी धुसूपैर करने की विजय कर रहा है।

उसके खिलाफ वैसी कोई कारबाई करने पर विचार किया जाना चाहिए, जैसा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से की गई थी। पाकिस्तान केवल जम्मू-कश्मीर को अंशों एवं अस्थिर रखने का ही प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि यहां के साथ-साथ पंजाब और राजस्थान में द्वाने के जरिये नशीले पदार्थ भी भेज रहा है।

**हाल के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को अंगेश्वा से कमतर प्रदान को लेकर भाजपा ने गहन मंथन शुरू किया है।**



डॉ. एशोक कुमार

यदि भाजपा ने उत्तर प्रदेश के परिणामों को समझो दिया संगठन या सरकार में किसी कोई बदलाव का निर्णय लिया तो वह उसके लिए आत्मघाती हो सकत है।

**हाल के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा ने गहन मंथन शुरू किया है।** पार्टी की विजय की लोकप्रियता में 10 से 21 प्रतिशत प्रदानमंत्री में 20 प्रतिशत की विजय लिया तो उसके समर्थन में 29.2 प्रतिशत को जरदार बढ़िया हुई, जो 14 प्रतिशत से बढ़कर 43.2 प्रतिशत हो गया।

प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता भी 62

प्रतिशत से घटकर 43 प्रतिशत हो गई।

शहरी और आर्मीनग क्षेत्रों में भाजपा-राजग

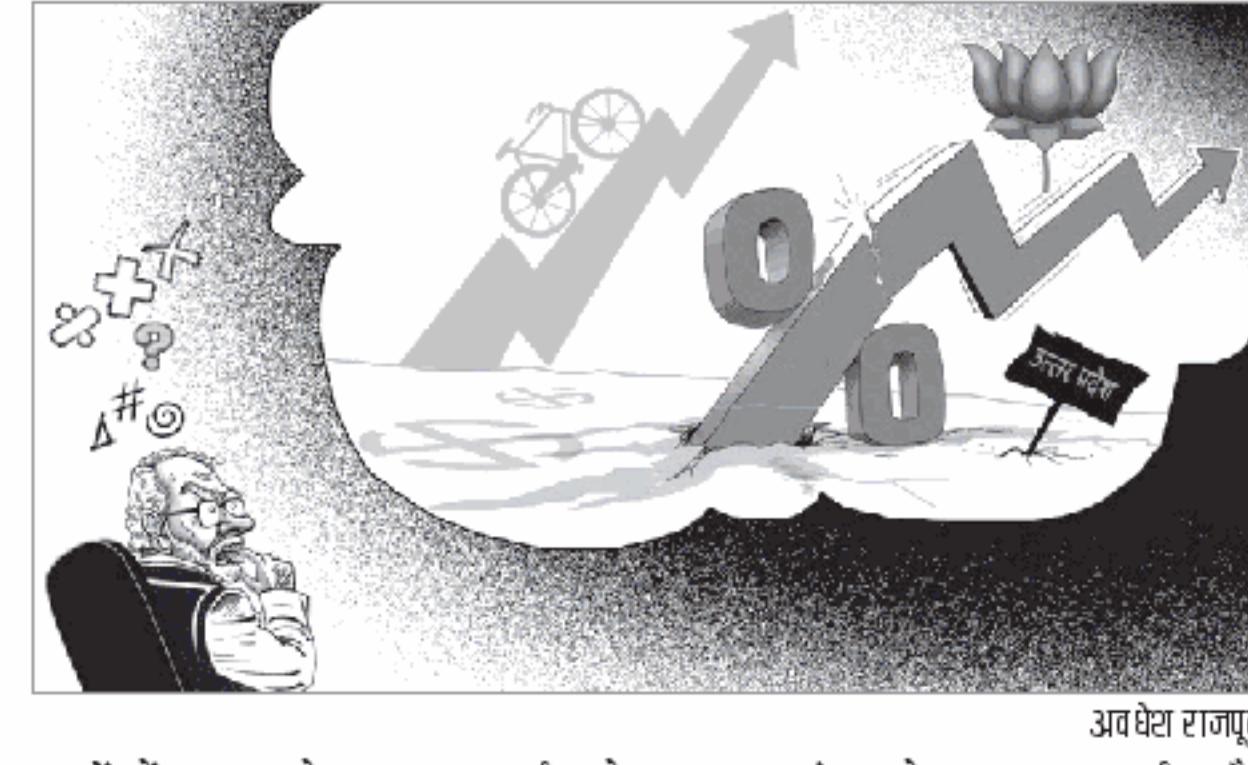
यूनी में पिछले प्रदान ही दोहरा लेती तो

आगे सिरे न चढ़ पाए, क्योंकि समय के साथ स्थितियों स्पष्ट होती जाएंगी और वह भी किसी से छिपा नहीं कि दिलत स्पात और बोली की विजय लिया होता है।

सर्वानुसार विजयी दैरेट वैद्य निर्णय लिया तो आगामी चुनावों में वह पार्टी के लिए आत्मघाती हो सकता है।

**सेंटर पार द स्ट्रीट आप संसायटी में हमें लोकसभा चुनावों के उल्लेख धूम्रपान के संदर्भ में उत्तर प्रदेश को लेकर दो अध्ययन किए।**

पहला अध्ययन जनवरी-मार्च में चुनाव पूर्व तथा दूसरा अप्रैल-जून में प्रत्येक चरण के मतदान के बाद किया गया। चुनाव पूर्व अध्ययन में 61 प्रतिशत उत्तरदाता भाजपा-राजग सरकार और 62



शुरू की। इसके चलते उत्तर प्रदेश में एक समय 15 से 17 प्रतिशत शेयरों तक सिमटी भाजपा को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सबका-संवाद-विकास एवं हकीकत बन गया था और समावेशी विकास अंतिम कठार में खड़े गयी थीं तक पहुंचा।

उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की अस्मिता बाली राजनीति के चलते भ्रष्टाचार, आई-पर्टीजनावाद और अपराधीकरण पूर्व से सिमटा में इनमा गहरी दैरेट बुला दी गई कि आज भी साशंका दैरेट बुला दी गई कि विजय लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए जारी राजनीति विवरण देखें जाएं।

उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की अस्मिता बाली राजनीति के चलते भ्रष्टाचार, आई-पर्टीजनावाद और अपराधीकरण पूर्व से सिमटा में इनमा गहरी दैरेट बुला दी गई कि विजय लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए जारी राजनीति विवरण देखें जाएं।

उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की अस्मिता बाली राजनीति के चलते भ्रष्टाचार, आई-पर्टीजनावाद और अपराधीकरण पूर्व से सिमटा में इनमा गहरी दैरेट बुला दी गई कि विजय लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए जारी राजनीति विवरण देखें जाएं।

उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की अस्मिता बाली राजनीति के चलते भ्रष्टाचार, आई-पर्टीजनावाद और अपराधीकरण पूर्व से सिमटा में इनमा गहरी दैरेट बुला दी गई कि विजय लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए जारी राजनीति विवरण देखें जाएं।

उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की अस्मिता बाली राजनीति के चलते भ्रष्टाचार, आई-पर्टीजनावाद और अपराधीकरण पूर्व से सिमटा में इनमा गहरी दैरेट बुला दी गई कि विजय लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए जारी राजनीति विवरण देखें जाएं।

उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की अस्मिता बाली राजनीति के चलते भ्रष्टाचार, आई-पर्टीजनावाद और अपराधीकरण पूर्व से सिमटा में इनमा गहरी दैरेट बुला दी गई कि विजय लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए जारी राजनीति विवरण देखें जाएं।

उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की अस्मिता बाली राजनीति के चलते भ्रष्टाचार, आई-पर्टीजनावाद और अपराधीकरण पूर्व से सिमटा में इनमा गहरी दैरेट बुला दी गई कि विजय लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए जारी राजनीति विवरण देखें जाएं।

उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की अस्मिता बाली राजनीति के चलते भ्रष्टाचार, आई-पर्टीजनावाद और अपराधीकरण पूर्व से सिमटा में इनमा गहरी दैरेट बुला दी गई कि विजय लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए जारी राजनीति विवरण देखें जाएं।

उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की अस्मिता बाली राजनीति के चलते भ्रष्टाचार, आई-पर्टीजनावाद और अपराधीकरण पूर्व से सिमटा में इनमा गहरी दैरेट बुला दी गई कि विजय लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए जारी राजनीति विवरण देखें जाएं।

उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की अस्मिता बाली राजनीति के चलते भ्रष्टाचार, आई-पर्टीजनावाद और अपराधीकरण पूर्व से सिमटा में इनमा गहरी दैरेट बुला दी गई कि विजय लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए जारी राजनीति विवरण देखें जाएं।

उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की अस्मिता बाली राजनीति के चलते भ्रष्टाचार, आई-पर्टीजनावाद और अपराधीकरण पूर्व से सिमटा में इनमा गहरी दैरेट बुला दी गई कि विजय लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए जारी राजनीति विवरण देखें जाएं।

उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की अस्मिता बाली राजनीति के चलते भ्रष्टाचार, आई-पर्टीजनावाद और अपराधीकरण पूर्व से सिमटा में इनमा गहरी दैरेट बुला दी गई कि विजय लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए जारी राजनीति विवरण देखें जाएं।

उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की अस्मिता बाली राजनीति के चलते भ्रष्टाचार, आई-पर्टीजनावाद और अपराधीकरण पूर्व से सिमटा में इनमा गहरी

## खनिज पर हक के

द्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को लेकर कई बार विवाद उठ चुके हैं। केंद्रीय कर प्रणाली जीएसटी लागू होने के बाद भी कुछ चीजों पर करों और उपकरों के बंटवारे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। खनिजों के स्वामित्व का प्रश्न भी उनमें एक है। केंद्र सरकार ने खनिजों पर कर और उपकर लगाना शुरू किया, तो कुछ कंपनियों और राज्य सरकारों ने इस पर सवाल उठाए। अधिकारकर सर्वोच्च न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है खनिजों पर राज्य सरकारों का हक होता है। वे उनका पट्टा देने को स्वतंत्र हैं। इसके लिए किए गए करार की एवज में वे जो शुल्क प्राप्त करती हैं, उसे कर नहीं कहा जा सकता। वह रायलटी की श्रेणी में आता है। रायलटी को कर नहीं कहा जा सकता। इस फैसले से खासकर ओडीशा और झारखण्ड को बड़ी रात मिली है। हालांकि करीब पैरीस वर्ष पहले भी एक सीमेंट कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला उठाया था कि केंद्र सरकार उससे उपकर नहीं वसूल सकती। तब अदालत ने कहा था कि खनिजों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। मगर दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने करीब बोस वर्ष पहले उस फैसले को पलटते हुए कहा कि पुराना फैसला छापे की गलती से भ्रामक हो गया था। केंद्र को खनिजों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है।

अब नौ न्यायाधीशों की पीट ने इस मामले पर बहुमत से फैसला दिया है कि खनिजों पर राज्य सरकारों का अधिकार है। दरअसल, यह मामला इसलिए उलझा हो आया कि संविधान में केंद्र को खदानों के आवंटन से संबंधित सीमाएं तथा करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। मगर जमीन, भवन आदि पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्य सरकारों की है। इसलिए केंद्र सरकार खनिजों पर कर लगाने लगी थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि खनिज राज्य सरकार की संपदा है, इसलिए वह उसके पहुंच की कीमत तथा कर सकती है। अगर खनिजों पर भी केंद्र सरकार कर वसूलने लगेगी, तो राज्यों को अपनी विकास परियोजनाओं के लिए धन युटाना मुश्किल हो जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य सरकारें क्रेंड्र द्वारा वसूला गया कर वापस दिलाने की गुहार लगा रही है। हालांकि इसका निपटारा किस प्रकार होगा, देखने की बात है।

राज्य सरकारों में असर इस बात को लेकर असंतोष देखा जाता है कि केंद्र को जिस अनुपात में उनसे राजस्व प्राप्त होता है, उस अनुपात में उन्हें बजटीय आवंटन नहीं मिलता। जबसे जीएसटी लागू हुआ है, राज्यों में अपने हिस्से का राजस्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष उभरता रहा है। इस तरह कई राज्यों में विकास परियोजनाएं ठहर जाती हैं। जाहिर है, सर्वोच्च न्यायालय के तजा फैसले के बाद उन राज्यों को अपना राजस्व युटाने में काफी मदद मिलेगी, जहां खनिज पदार्थों की बहुलता है। ओडीशा, मध्यप्रदेश, झारखण्ड आदि राज्यों में कायला, सीमेंट, तौह अयस्क, पेट्रोलियम आदि पदार्थों की खदान हैं, मगर वे उनका पूरा लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि उन पर अपील तक केंद्र सरकार भी अपना हक जाताई आ रही थी। यह ठीक है कि राज्यों से प्राप्त राजस्व से ही केंद्र सरकार पूरे देश की विकास परियोजनाओं में संतुलन कायम करती है, मगर उनकी आय के निजी स्रोत नहीं होंगे, तो वे केंद्र के सामने हर वक्त याचक की मुद्रा में ही होंगी। इसलिए खनिज संपन्न राज्यों में कुछ बेतरी की उम्मीद जगी है। मगर केंद्र को खनिजों के मनमाने दोहन पर नजर तो रखनी ही होगी।

## जानलेवा रफ्तार

इक हादसों में ज्यादातर की वजह कुछ वाहन चालकों की ऐसी लापरवाही होती है, जिसमें इस बात का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि अन्य व्यक्ति के जीवन का भी कोई नील है। यह सही है कि बहुत सारे लोग सड़क पर सावधानी और जिम्मेदारी से वाहन चालते हैं और इस तरह वे सड़क पर सफर कर रहे अन्य लोगों के साथ-साथ अपनी जिंदगी की भी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मगर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो शायद यह मान कर चलते हैं कि उनके लिए दूसरों के जीवन की कोई अहमियत नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा में बुधवार की रात तीन लोग सड़क के किनारे सो रहे थे, तब एक वाहन चालक उन तीनों को बुरी तरह कुचल कर फरार हो गया। उनमें से दो की मौत हो गई, तीसरा बुरी तरह घायल हो गया। इतना तय है कि हादसे के शिकार लोगों के पास शायद फिलहाल वही ठिकाना था और वे सड़क किनारे की किसी जगह को सुरक्षित मान कर वहां सो रहे थे। अगर किसी बेलगाम वाहन ने उन्हें कुचल डाला, तो इसे चालक की आपाधिक लापरवाही ही कहा जाना चाहिए।

निश्चित रूप से सड़कों के किनारे आसपास की जगहें सोने के लिए नहीं होती हैं और वहां हमेशा जोखिम बना रहता है। मगर एक समस्या यह है कि महानारों में रोजी-रोटी की तलाश में आए किसी व्यक्ति के पास अगर पैसे का अभाव या किसी मजबूरी की वजह से रहने का फुटपाथ पर सोना पड़ जाता है। सरकार की ओर से घोषित तौर पर रेन बर्से जैसी व्यवस्था है, लेकिन वह वह बेघर लोगों की संख्या के लियाज से अपर्याप्त है या फिर इस कदर कुव्वतव्यस्था का शिकार है कि वहां ज्यादातर लोग नहीं जाना चाहते। अक्सर ऐसे हादसों की खबरें आती रहती हैं, जिनमें किसी वाहन चालक की लापरवाही की वजह से फुटपाथ पर सो रहे लोगों की कुचल कर मौत हो गई। यह समझना मुश्किल है कि इस पर मौजूद और जैसी व्यक्ति को कितनी हड्डबड़ी और कैसी बेफिक्री होती है कि उसे सड़क पर मौजूद अच्युत लोगों की जिंदगी और हालात की अहमियत समझना जरूरी नहीं लगता।

## खेती में मुनाफे की नई पहल

दुनिया में वैज्ञानिक तथा तकनीक पद्धति से खेती करना समझदारी और लाभकर समझा जाता है। इसी के जरिए केंद्र सरकार की नई

### अधिलेश आर्यदु

ए

क वार फिर केंद्र सरकार किसानों की माली हालात सुधारने की पहल करती दिख रही है। सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि किसानों को किसानी के जरिए ही अब उद्यमी बनाया जाएगा, इससे किसानों की माली हालात में सुधार होगा। आमतौर पर भारतीय खेती को परपरा से की जाने वाली देसी खेती माना जाता है। मगर यह महज मान्यता है, क्योंकि देसी खेती में रसायनों, रासायनिक उद्यरकों और विदेशी बीज की इस्तेमाल नहीं होता। नई तकनीक तथा वैज्ञानिक ढंग से की जाने वाली खेती में रसायनों और महारों उद्यरकों का इस्तेमाल उत्पादन के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार की नई



रूप में इस्तेमाल के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसे किसानों का चयन टीम करेंगी, जो बेहतर उत्पाद और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती कर दूसरे किसानों के लिए नए नीज बन सकते हैं।

केंद्र सरकार ने पिछले शासन के लिए कई

त जुर्बेकारों का कहना है कि केंद्र सरकार अग्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर रासायनिक खेती मुक्त भारत का अभियान चलाए तो जलवायु परिवर्तन, बढ़ती वीमारियों, प्रदूषणों तथा अच्युतस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए किसानों को उद्यमी बनाने का बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार के जरिए उद्यरकों पर हड्ड के बावजूद और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती करना की जरूरत है। जिससे उद्यरकों, बीजों और छिड़काव करने वाले यंत्रों पर दी जाने वाली अरबों रुपए की सबसिडी की बचत होगी और देश की सेहत सुधारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, गांवों की गरीबी दूर होगी, खुम्खाएं, कुपोषण, अशक्ति, बोरेजारी और पलायन जैसी समस्याओं से धीरे-धीरे छुटकारा मिलने लगेगा।

भारत उत्पादन के लिए यह बात अपनाया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय खेती के लिए यह घाटे का सोचा है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के जरिए उद्यरकों पर हड्ड के बावजूद किसानों की जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती करना की जरूरत है। उसके उत्पादक नहीं किया जाना चाहिए। जिससे उद्यमी बनाने का बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए।

गैरललव वैतावर्ष 2022-23 में 123 अरब भारतीय रुपए से अधिक मूल्य के उद्यरकों का आया किया गया। केंद्र सरकार के जरिए उद्यरकों पर हड्ड के बावजूद किसानों की जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर भी गैरललव की जरूरत है। इसलिए गसायनिक खेती की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर भी गैरललव की जरूरत है। नामांत्र की लागत में अधिक उत्पादन और जलवायु परिवर्तन के असर की कम करने में प्राकृतिक खेती की सहायता ज्यादा फायदेमंद और उपयोगी है, इसकी की जाना चाहिए।

इस वर्तन में खेती की रसीदी और उद्यमी बनानी जानी है। इसमें लागत बहुत मात्रा में शामिल है। और न यह सेहत के लिए ही उपयोग की जानी चाहिए। इसमें लागत में बेहतर उत्पाद देने वाली प्राकृतिक खेती को हर तरह से व्यापक किया जाना चाहिए। जिस तरह कारखानों के घटे की भरपूर उत्पादन करती है, इसी तरह किसानों की खेती में घटा होने पर भरपूर की जानी चाहिए। एसएस स्वामीनाथन की न्यूतम समस्याएँ सूखंसंघर्ष पूर्वाग्रह द्वारा लागत हो रही है। बल्कि समाज से भी अनेक तरह की किसानों की जानी चाहिए। इससे देश का किसान ही खुशबूल नहीं होगा, बल्कि समाज से भी अनेक तरह की समस्याओं, दुश्वारियों और बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है।

## पूर्वग्रहों की जंजीरें

### खुशी श्रीवास्तव



पांच अंतरराष्ट्रीय संगठनों की संयुक्त रिपोर्ट का यह कहना बेद गंभीर है कि दुनिया का हर ग्राहवां व्यक्ति भुखमी से ज़ब्द रहा है। चरम मौसमी घटनाएं जिस तरह उत्पादन पर असर डाल रही हैं, उसे देखते हुए सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक समुदाय के मिलकर काम करने की ज़रूरत ज्यादा बढ़ गई है।

## ताकि कोई भूखा न रहे

द

निया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की नीतिनाम रिपोर्ट ने हमारे समने पुनः एक कठोर सचिवाई को उत्पादन किया है कि दुनिया का हर ग्राहवां शख्स भुखमी से ज़ब्द रहा है।

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कांग, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से ज़रीरी रिपोर्ट 'द स्टेट ऑफ फूल सिक्योरिटी ऐड न्यूट्रिशन' बताती है कि वर्ष 2024 में कीरी 73 करोड़ लोग खाली पेट सोने को मजबूर थे।

चिंता की बात है कि 2019 की तुलना में इस संख्या में 15.2 करोड़ की बढ़ोतारी हुई है, लेकिन बड़ी चिंता इस तथ्य को लेकर होनी चाहिए कि पिछले तीन वर्षों से यह अंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट की इस चेतावनी को भी धौंसता करने की ज़रूरत है कि दुनिया 2030 तक भूख को शून्य के स्तर पर ले जाने के समर्थन करें।

से काफी पैछे रह गई है। अप्रीका या लैटिन अमेरिका के मुकाबले एशिया में भूख का समान करने वाली आवादी का प्रतिशत बेशक स्थिर है, लेकिन यह दुनिया भर में भूख का समान करने वाले आधे से ज्यादा लोगों का रह इसलिए यह चिंताजनक है। ये अंकड़े दर्शाते हैं कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर हमारी नीतियां और योजनाएं अब तक पर्याप्त समित तो नहीं ही हुई हैं, कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय संर्वांजीक कारोबारों को और भी गहरा कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, स्वस्थ आहार का तक अधिक पूँच की कमी भी एक अधिक मुद्दा है, जिससे वैश्विक आवादी का कीरी बढ़ावा देने के लिए वैश्विक समुदाय के मिलकर काम करने की ज़रूरत ज्यादा बढ़ गई है। विश्वव्यापी समस्या बन चुकी भुखमी से निपटने के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग व संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण महत्वपूर्ण है, साथ ही, खाद्य उत्पादन और वितरण की प्रणाली में सुधार की भी ज़रूरत है, ताकि यह यह सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे।



## आखिर द्रमुक की समस्या क्या है

द्रमुक अलगाववादी संस्कृति को बढ़ावा देती है। यदि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में तमिलनाडु का उल्लेख नहीं किया है, तो इसका यह मतलब नहीं कि द्रमुक अन्य दक्षिणी राज्यों को नीति आयोग की बैठक में भाग लेने से रोके। 2004 से 2014 के बीच यूपीए के छह बजट भाषणों में तमिलनाडु का उल्लेख नहीं किया गया।

मुक, वाईएस अकांग्रेस और माकपा जैसे दक्षिणी राजनीतिक दल केंद्रीय बजट को लॉड-मोरोड़कर उत्पक्ष के विशेषण कर रहे हैं और संकीर्णतावाद तथा क्षेत्रीयतावाद को भड़का रहे हैं। इंडिया गढ़वां और समीक्षीय राजनीतिक दलों ने प्रभावी ढंग से एक आखिरी पांच विकास नियमों को दिया है।



इसका कारण यह है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश से सदा हुआ राज्य है।

जाने-मात्र अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अच्युत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जब कोई अर्थशास्त्री और वहां वाली है, तो उसका वित्त मंत्री भी बजटीय अत्यावश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। 8.2 फीसदी जीडीपी वृद्धि, कर प्राप्तियों में निरंतर उछाल और रिजर्व बैंक से संपर्क लाभार्थी की बढ़ती विविधार करके द्रमुक खुले आलग थलग महसूस कर रही है।

द्रमुक कोंग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गढ़वां का हिस्सा है, जिसने भाजपा के अवकाश वाले 400 पार के नारे को भारी झटका दिया और दक्षिणी राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की टिप्पणी एसे बल में आई है, जब विपक्षी नेताओं ने बजट पर निर्भावक और बदल से जारी कर रही है।

जाने-मात्र अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अच्युत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जब कोई अर्थशास्त्री और वहां वाली है, तो उसका वित्त मंत्री भी बजटीय अत्यावश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है।

द्रमुक कोंग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गढ़वां का हिस्सा है, जिसने भाजपा के अवकाश वाले 400 पार के नारे को भारी झटका दिया और दक्षिणी राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की टिप्पणी एसे बल में आई है, जब विपक्षी नेताओं ने बजट पर निर्भावक और बदल से जारी कर रही है।

द्रमुक कोंग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गढ़वां का हिस्सा है, जिसने भाजपा के अवकाश वाले 400 पार के नारे को भारी झटका दिया और दक्षिणी राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की टिप्पणी एसे बल में आई है, जब विपक्षी नेताओं ने बजट पर निर्भावक और बदल से जारी कर रही है।

द्रमुक कोंग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गढ़वां का हिस्सा है, जिसने भाजपा के अवकाश वाले 400 पार के नारे को भारी झटका दिया और दक्षिणी राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की टिप्पणी एसे बल में आई है, जब विपक्षी नेताओं ने बजट पर निर्भावक और बदल से जारी कर रही है।

द्रमुक कोंग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गढ़वां का हिस्सा है, जिसने भाजपा के अवकाश वाले 400 पार के नारे को भारी झटका दिया और दक्षिणी राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की टिप्पणी एसे बल में आई है, जब विपक्षी नेताओं ने बजट पर निर्भावक और बदल से जारी कर रही है।

द्रमुक कोंग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गढ़वां का हिस्सा है, जिसने भाजपा के अवकाश वाले 400 पार के नारे को भारी झटका दिया और दक्षिणी राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की टिप्पणी एसे बल में आई है, जब विपक्षी नेताओं ने बजट पर निर्भावक और बदल से जारी कर रही है।

द्रमुक कोंग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गढ़वां का हिस्सा है, जिसने भाजपा के अवकाश वाले 400 पार के नारे को भारी झटका दिया और दक्षिणी राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की टिप्पणी एसे बल में आई है, जब विपक्षी नेताओं ने बजट पर निर्भावक और बदल से जारी कर रही है।

द्रमुक कोंग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गढ़वां का हिस्सा है, जिसने भाजपा के अवकाश वाले 400 पार के नारे को भारी झटका दिया और दक्षिणी राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की टिप्पणी एसे बल में आई है, जब विपक्षी नेताओं ने बजट पर निर्भावक और बदल से जारी कर रही है।

द्रमुक कोंग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गढ़वां का हिस्सा है, जिसने भाजपा के अवकाश वाले 400 पार के नारे को भारी झटका दिया और दक्षिणी राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की टिप्पणी एसे बल में आई है, जब विपक्षी नेताओं ने बजट पर निर्भावक और बदल से जारी कर रही है।

द्रमुक कोंग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गढ़वां का हिस्सा है, जिसने भाजपा के अवकाश वाले 400 पार के नारे को भारी झटका दिया और दक्षिणी राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की टिप्पणी एसे बल में आई है, जब विपक्षी नेताओं ने बजट पर निर्भावक और बदल से जारी कर रही है।

द्रमुक कोंग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गढ़वां का हिस्सा है, जिसने भाजपा के अवकाश वाले 400 पार के नारे को भारी झटका दिया और दक्षिणी राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की टिप्पणी एसे बल में आई है, जब विपक्षी नेताओं ने बजट पर निर्भावक और बदल से जारी कर रही है।

द्रमुक कोंग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गढ़वां का हिस्सा है, जिसने भाजपा के अवकाश वाले 400 पार के नारे को भारी झटका दिया और दक्षिणी राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की टिप्पणी एसे बल में आई है, जब विपक्षी नेताओं ने बजट पर निर्भावक और बदल से जारी कर रही है।

द्रमुक कोंग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गढ़वां का हिस्सा है, जिसने भाजपा के अवकाश वाले 400 पार के नारे को भारी झटका दिया और दक्षिणी राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की टिप्पणी एसे बल में आई है, जब विपक

